रवींद्र तुकाराम हिवाले

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1419-1420/2010)

अगस्त 2, 2010

[हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली केआर प्रसाद, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 306 और 498-ए-एक विवाहित महिला जो खुद को जलाकर स्वयं की मौत का कारण बनती है-पति को यू/एस 306 और 498-ए के तहत दोषी ठहराया और क्रमशः चार साल और एक साल के आर. आई. की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने यू/एस 306 के तहत सजा को बढ़ाकर छह साल कर दिया- अभिनिर्धारित:मृतक द्वारा की गई मृत्यु घोषणा के प्रकाश में कि उसने उसी सुबह यानी घटना की तारीख अपने पति के साथ झगड़ा किया था,(जो कि युवा विवाहित जोड़ों के बीच होने वाली एक आम बात है), उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में उचित नहीं माना कि आरोपी अपनी झगड़ालू प्रकृति के कारण सजा में वृद्धि के लिए उत्तरदायी था-इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि सजा की मात्रा पर अपीलीय अदालत का हस्तक्षेप दुर्लभ होना चाहिए और केवल असाधारण मामलों में-धारा 306 एक सजा का प्रावधान करती है जो 10 साल तक बढ़ सकती है और 10 साल तक की सजा सुनाने के लिए निचली अदालत का विशेषाधिकार था-सुनवाई अदालत ने एक सकारात्मक निष्कर्ष निकाला कि आरोपी की ओर से कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था और यह घटना सुबह के पारिवारिक झगड़े के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक घटना थी। घटना से लगभग एक साल पहले

लिखे गए दो पत्रों के आधार पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष का मृतक की मृत्यु घोषणा के आलोक में बहुत कम मूल्य होगा, यह घटना फरवरी, 1990 में हुई थी और अपीलार्थी लगभग चार साल की सजा काट चुका है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हैं और निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा की मात्रा में दखल अंदाजी-सजा का औचित्य।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1419-1420/2010

बॉम्बे उच्च न्यायालय, बेंच नागपुर नागपुर पीठ के आपराधिक अपील संख्या 53/1991 और 199/1991 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2006 से उत्पन्न।

बी. श्रीधर अपीलार्थी के लिए।

प्रत्यर्थी के लिए शंकर चिल्लरगी, आशा जी. नायर, रवींद्र केशवराव अड़सुरे।

न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि -

आदेश

अनुमति दी गयी।

अपीलार्थी का विवाह उसकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद मृतक अलका के साथ हुआ था।अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार 6 फरवरी, 1990 को सुबह लगभग 7 बजे मृतक को घर की रसोई में गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं और अंततः उन चोटों से उसकी मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष का मामला है कि 9 फरवरी 1990 को सुबह लगभग 8:30 बजे उसने एक पुलिस हेड कांस्टेबल को मौत की घोषणा की, जिसमें उसने कहा कि उसका अपने पति के साथ घर के कामों और बच्चों को खिलाने

को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद उसने खुद पर मिट्टी का तेल डाला और फिर खुद को जला लिया।

निचली अदालत ने साक्ष्य पर विचार करने पर अपीलार्थी को धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराधों और एक साल की सजा और धारा 306 के तहत चार साल की सजा का दोषी ठहराया।इसके बाद अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जबकि महाराष्ट्र राज्य ने भी उच्च सजा के लिए अपील दायर की।याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया और निचली अदालत द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 306 के तहत दी गई सजा को चार साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया।इस स्थिति में मामला हमारे सामने है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने केवल एक तर्क दिया है।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि अपीलकर्ता झगड़ालू और आक्रामक प्रकृति का प्रतीत होता है और उसके व्यवहार के साक्ष्य के रूप में दो पत्रों पर भरोसा किया गया था जिसमें भारी सजा की आवश्यकता थी।हालाँकि, हम देखते हैं कि मृतक द्वारा उस सुबह की गई मृत्यु घोषणा के आलोक में कि उसने अपने पति के साथ झगड़ा किया था (जो कि युवा विवाहित जोड़ों के बीच होने वाली एक आम बात है), उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में उचित नहीं था कि अपीलार्थी अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण सजा में वृद्धि के लिए उत्तरदायी था।हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि सजा की मात्रा पर अपीलीय अदालत का हस्तक्षेप दुर्लभ और केवल असाधारण मामलों में होना चाहिए।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 366 में एक सजा का प्रावधान है जो 10 साल तक बढ़ सकती है। इसलिए 10 साल तक की सजा सुनाना निचली अदालत का विशेषाधिकार था।जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है,

निचली अदालत ने एक सकारात्मक निष्कर्ष दिया था कि अपीलार्थी की ओर से कुछ समय तक कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था और यह घटना सुबह के पारिवारिक झगड़े से उत्पन्न हुई थी।घटना से लगभग एक साल पहले लिखे गए दो पत्रों के आधार पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष का मृतक की मृत्यु घोषणा के आलोक में बहुत कम मूल्य होगा। हम यह भी देखते हैं कि यह घटना फरवरी,1990 में हुई थी और हमें विद्वान न्यायमित्र द्वारा बताया गया है कि अपीलार्थी लगभग चार साल की सजा काट चुका है।

हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हैं और निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हैं।इस बीच, हम यह भी निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी जो हिरासत में है, उसे किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत रिहा कर दिया जाए।

अपील की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।